सामग्री प्रबंधन

प्रो मनोज चौधरी

# गति से प्रगति तक
# विकसित भारत के लिए लॉजिस्टिक्स क्रांति

***प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, भारत ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति की है और आज हमारा लॉजिस्टिक्स क्षेत्र अपने आर्थिक रूपांतरण के एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है।***

परिवहन और लॉजिस्टिक्स किसी भी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ होते हैं। हम जिस भी वस्तु का उपभोग करते हैं, जो भी यात्रा करते हैं और जिन शहरों में रहते हैं, वे सब लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की सुचारु आवाजाही पर निर्भर हैं।

## लॉजिस्टिक्स: विकास और सुरक्षा की आधारशिला

**'लॉजिस्टिक्स' का अर्थ है- उत्पादन और उपभोग के बीच वस्तुओं का परिवहन और प्रबंधन, भंडारण, मूल्य संवर्द्धन और संबद्ध सेवाएं।**

चाहे लक्ष्य हमारी उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मकता को बेहतर बनाना हो या घरेलू मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना- दोनों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स प्रणाली हमारे भविष्य की रीढ़ है। लॉजिस्टिक्स सेवाएं जितनी मज़बूत होंगी, हमारी सीमाएं उतनी ही सुरक्षित रहेंगी। किसी भी सैन्य अभियान की सफलता के लिए 'संसाधनों का कुशल प्रबंधन' एक अनिवार्य कसौटी है। युद्ध, आपात स्थिति या वैश्विक महामारी के समय में, मज़बूत लॉजिस्टिक्स शृंखला वाले देश ही 'स्थिर, सुरक्षित और सक्षम' साबित हुए हैं। इसलिए, चाहे आर्थिक विकास हो या रक्षा उद्देश्य- लॉजिस्टिक्स एक केंद्रीय विषय बन गया है, क्योंकि इसका जीडीपी वृद्धि पर गुणक प्रभाव पड़ता है। इस दशक की उथल-पुथल जैसे- महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया संकट आदि ने लचीली आपूर्ति शृंखलाओं और लॉजिस्टिक्स सक्षमता पर ध्यान और तीव्र कर दिया है।

## अवसंरचना विस्तार की नई गति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, भारत ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति की है। आज हमारा लॉजिस्टिक्स क्षेत्र अपने आर्थिक रूपांतरण के एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। पिछले एक दशक में, देश ने एक महत्त्वाकांक्षी अवसंरचना आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया है, जो रेलवे, फ्रेट लॉजिस्टिक्स, राजमार्ग, माल ढुलाई गलियारों, बंदरगाहों, समुद्री क्षेत्र, विमानन, एकीकृत योजना ढांचे और डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्रणालियों में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश से संचालित है। इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

- **रेलवे:** हमारे ब्रॉड गेज नेटवर्क का लगभग 100 प्रतिशत विद्युतीकरण, वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत, रेलवे स्टेशनों को आर्थिक केंद्रों में बदलने के लिए अमृत भारत स्टेशन पुनर्विकास,

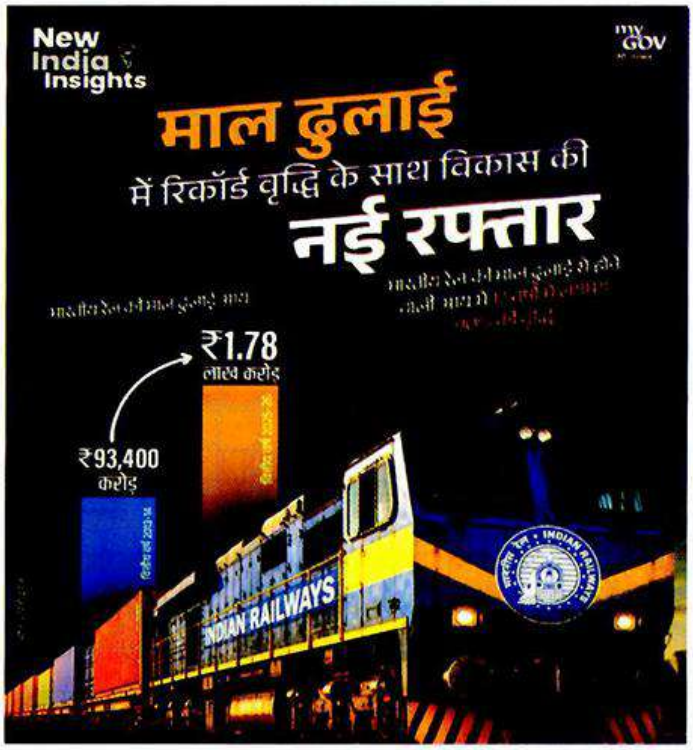


*लेखक गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। ईमेल: vicechancellor@gsv.ac.in*

स्वदेशी लोकोमोटिव और कोच विनिर्माण का विस्तार, पहली बार जम्मू-कश्मीर और मिज़ोरम में रेल संपर्क, 'कवच' जैसी स्वदेशी तकनीकों से सुरक्षा में सुधार तथा सोनीपत-जींद मार्ग पर देश की पहली हाइड्रोजन-चालित ट्रेन।

- **समर्पित माल ढुलाई (फ्रेट) गलियारे :** जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) तक संपर्क के साथ 2843 किमी के पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे। इससे माल और यात्री ट्रेनों का पृथक्करण संभव हुआ, जिससे गति और क्षमता दोनों में बढ़ोतरी हुई है।
- **उच्च गति ट्रेन (बुलेट ट्रेन):** अहमदाबाद और मुंबई (508 किमी) के बीच 320 किमी/घंटा की गति से पहली बुलेट ट्रेन, जिसका पहला चरण 2027 में शुरू होने की योजना है।
- **राजमार्ग और एक्सप्रेसवे:** भारतमाला (22,500+ किमी), राजमार्ग नेटवर्क का 1.46 लाख किमी तक विस्तार और एक्सप्रेसवे (3,052+ किमी)। प्रवेश-नियंत्रित एक्सप्रेसवे आवागमन का एक नया साधन हैं और सड़क निर्माण में टिकाऊ प्रथाएं भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण हैं। गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा और दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।
- **विमानन:** 2014 में 74 से बढ़कर 2026 में 165 नागरिक हवाई अड्डे, टियर-II/टियर-III शहरों को जोड़ने के लिए 'उड़ान' योजना, सी-295 सैन्य परिवहन विमान जैसे विमान संयोजन संचालन की स्थापना और देश में एमआरओ (रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल) क्षेत्र स्थापित करने के लिए नीतियां। जेवर और नवी मुंबई में नए हवाई अड्डे बड़े शहरों की मांग को पूरा करने के उदाहरण हैं।
- **बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र:** प्रमुख बंदरगाहों पर टर्नअराउंड समय में उल्लेखनीय सुधार, वधावन में ग्रीनफील्ड बहु-माध्यमीय बंदरगाह की घोषणा, समुद्री विकास कोष के माध्यम से ज़हाज निर्माण की शुरुआत, और 'सागरमाला कार्यक्रम' जो बंदरगाह आधुनिकीकरण, बंदरगाह संपर्क और तटीय सामुदायिक विकास पर केंद्रित है। नौ भारतीय बंदरगाह अब विश्व के शीर्ष 100 बंदरगाहों की सूची में शामिल हैं।
- **जलमार्ग:** 111 राष्ट्रीय जलमार्ग अधिसूचित हैं, जिनसे 35 लाख से अधिक यात्रियों को लाभ मिल रहा है।
- **शहरी गतिशीलता:** मेट्रो का 26 शहरों (एक दशक पहले पांच से बढ़कर) और 1155 किमी तक विस्तार, मेट्रो नेटवर्क की चार गुना बढ़ोतरी, आरआरटीएस (क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) और बीआरटीएस (बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) की शुरुआत तथा एफएएमई (फास्टर एडॉप्शन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) के तहत इलेक्ट्रिक गतिशीलता विकल्पों में सुधार।

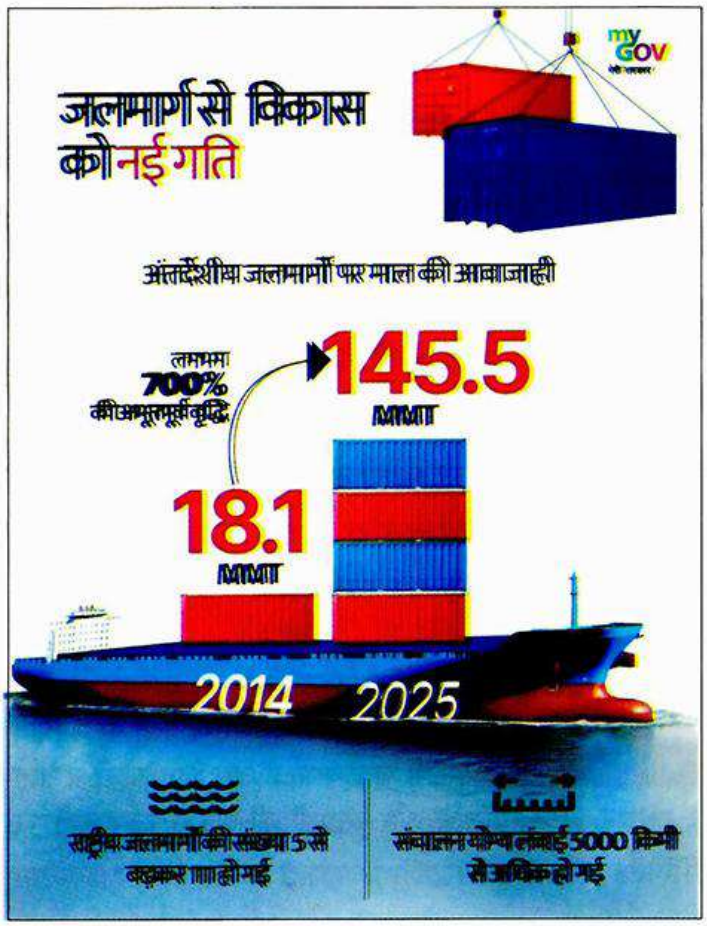


- **मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स पार्क:** 35 लॉजिस्टिक्स पार्क, 306 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल और इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना।
- **गति शक्ति विश्वविद्यालय:** परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए देश का पहला समर्पित विश्वविद्यालय।

## पीएम गति शक्ति: एकीकृत योजना का नया मॉडल

लॉजिस्टिक्स लागतों के प्रमुख घटकों में परिवहन और शिपिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, सूची प्रबंधन, भंडारण, सामग्री हैंडलिंग, पैकेजिंग और निगरानी आदि शामिल हैं। इन प्रत्येक घटक को व्यक्तिगत रूप और एक समग्र प्रणाली के दृष्टिकोण, दोनों से देखना आवश्यक है।

दो प्रमुख नीतिगत पहल जो इन अत्यंत तीव्र सुधारों की ओर ले जा रही हैं:

**पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (2021) :** यह भारत सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है, जिसका उद्देश्य अवसंरचना विकास को बदलना और देशभर में बहु-माध्यमीय संपर्क को बढ़ावा देना है। यह योजना 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण के तहत एक भू-स्थानिक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग, अंतर-मंत्रालयी बाधाओं को तोड़ने, एकीकृत योजना को प्रोत्साहित करने और लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने के लिए करती है। आज 58 केंद्रीय मंत्रालयों और 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 3,200 से अधिक डेटा स्तरों ने व्यक्तिनिष्ठ निर्णय लेने की जगह वस्तुनिष्ठ, डेटा-आधारित शासन को स्थापित किया है। यह एकीकृत 'एकल सत्य स्रोत' व्यापकता, प्राथमिकता

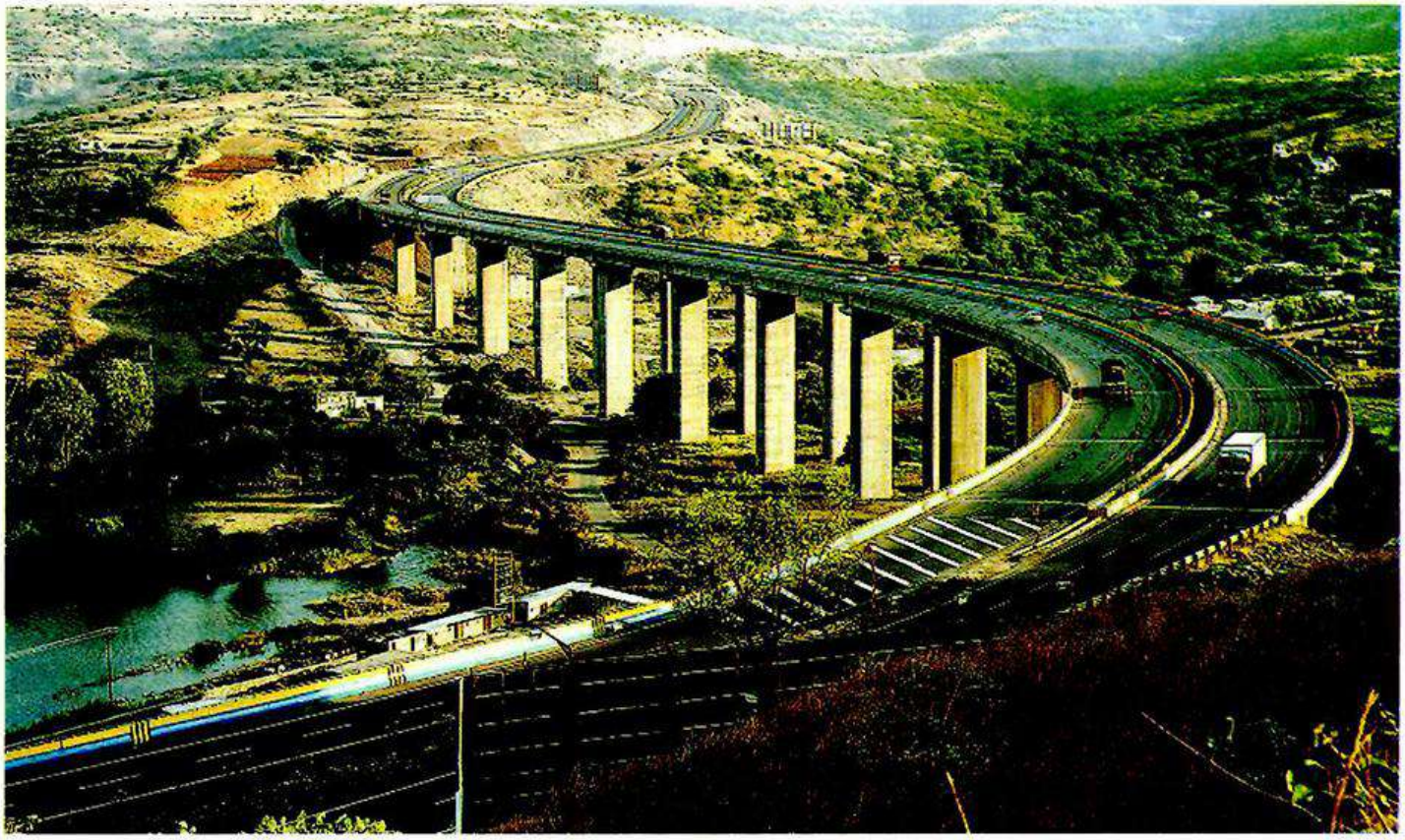

*पुणे-कात्रज राष्ट्रीय राजमार्ग*

निर्धारण, अनुकूलन, समन्वय, विश्लेषणात्मक गहराई और गतिशील रीयल टाइम एपीआई एकीकरण के प्रमुख स्तंभों के माध्यम से सक्षम किया गया है, जो निर्णयकताओं के लिए सटीक और समय पर जानकारी सुनिश्चित करता है। आज पीएम गति शक्ति का उपयोग भौतिक अवसंरचना परियोजनाओं (रेलवे, राजमार्ग, दूरसंचार, गैस पाइपलाइन, आदि) और सामाजिक अवसंरचना (विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा आदि) दोनों के लिए किया जा रहा है।

अपने लॉन्च के चार वर्षों के भीतर, पीएम गति शक्ति के माध्यम से 15 लाख करोड़ रुपये के लगभग 240 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है। राष्ट्रीय परियोजनाओं की कार्यवाही को तेज़ करने के लिए, 'प्रगति' (पीआरएजीएटीआई–प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लिमेंटेशन), परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान बाधाओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए कार्यरत है। यह मंच सुनिश्चित करता है कि परियोजनाएं राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हों और समय पर पूरी हों, जिससे देरी कम हो और लागत में वृद्धि न हो। यह एकीकरण भारत की 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह हरित बुनियादी ढांचे और सतत लॉजिस्टिक्स समाधानों के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। पीएम गति शक्ति का विस्तार देश के सभी जिलों में किया जा चुका है।

**राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022) :** देश में त्वरित समावेशी विकास के लिए 'एक प्रौद्योगिकी-सक्षम, एकीकृत, लागत-कुशल, लचीला, टिकाऊ और विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने' के दृष्टिकोण के साथ, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) 2022 बनाई गई। इस नीति में एक व्यापक कार्ययोजना शामिल है, जिसमें डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्रणालियों का एकीकरण, भौतिक संपत्तियों का मानकीकरण और सेवा गुणवत्ता मानकों की तुलनात्मक जांच, मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण, 'सहकारी संघवाद' की सच्ची भावना में राज्यों की भागीदारी, निर्यात-आयात (एक्जिम) लॉजिस्टिक्स पर विशेष ध्यान, लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार और आपूर्ति-मांग पक्ष की समस्याओं के समाधान के लिए क्षेत्रवार योजनाएं (जैसे कोयला, इस्पात, उर्वरक, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, सीमेंट आदि), लॉजिस्टिक्स पार्कों का विकास, आदि सम्मिलित हैं।

प्रमुख पहल में शामिल हैं:

- **एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफ़ॉर्म (यूएलआईपी):** यह लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक डिजिटल प्रवेश द्वार है, जो विभिन्न सरकारी प्रणालियों पर उपलब्ध डेटा तक पहुंच, ट्रैकिंग/ट्रेसिंग, प्रमाणीकरण, दस्तावेज़ डिजिटलीकरण, प्रक्रिया स्वचालन, डिस्कवरी सर्विसेज आदि को सक्षम बनाता है। सभी प्रकार के लॉजिस्टिक्स माध्यम (वायु/सड़क/रेल/बंदरगाह) कार्गो के प्रकार की परवाह किए बिना इसमें शामिल किए गए हैं।
- **लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (एलडीबी):** आरएफआईडी, आईओटी और बिग डेटा के माध्यम से सभी एक्जिम कंटेनरों की 100 प्रतिशत ट्रैकिंग सुनिश्चित करता है।

- **एलईएडीएस (विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सुगमता):** राज्यों को अपने प्रदर्शन की तुलना करने, सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने और अपनी भौगोलिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए निरंतर सुधार की दिशा में आगे बढ़ने में सक्षम बनाकर, उनमें प्रतिस्पर्धी संघवाद और सहकारी संघवाद, दोनों को सुदृढ़ करना।

## कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता

**द्वि-उपयोग अवसंरचना:** नीति लागत दक्षता और परिचालन लाभ सुनिश्चित कर रही है, क्योंकि अवसंरचना का निर्माण और उपयोग नागरिक और रक्षा दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, जिससे सैन्य-असैनिक सम्मिश्रण को बढ़ावा मिल रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग पूर्वानुमानित मांग मॉडलिंग, संसाधन पूर्वानुमान, परियोजना निगरानी और जोखिम प्रबंधन को सुनिश्चित करेगा।

**भंडारण क्षेत्र:** परिवहन लागत (जो सामान्यतः दूरी या माध्यम पर आधारित होती है) के विपरीत, भंडारण लागत वस्तु के प्रकार, भूमि व अवसंरचना की उपलब्धता, स्थान, भंडारण अवधि, प्रौद्योगिकी को अपनाने और परिचालन दक्षता जैसे कारकों से निर्धारित होती है। नाशवान वस्तुओं, दवाइयों और कुछ रसायनों के लिए उपयोग किए जाने वाले तापमान-नियंत्रित गोदाम, सामान्य दर से लगभग दोगुनी लागत पर आते हैं। इसी प्रकार, खतरनाक माल को संभालने वाली सुविधाओं पर अतिरिक्त सुरक्षा, विनियामक और अवसंरचना आवश्यकताओं के कारण औसतन अधिक लागत आती है। भंडारण क्षेत्र, डिजिटल ट्विन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और रोबोटिक्स का लाभ उठाते हुए, प्रौद्योगिकी-सक्षम आधुनिकीकरण और परिचालन दक्षता की दिशा में तेज़ी से बढ़ रहा है।

## लॉजिस्टिक्स में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा साइंस: एक परिवर्तनकारी बदलाव

आज परिवहन प्रणालियां, ट्रैफिक सेंसर, जीपीएस-सक्षम वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक टोल प्रणालियों, टिकटिंग प्लेटफ़ॉर्मों, निगरानी कैमरों, मौसम फीड और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन नेटवर्क से अभूतपूर्व मात्रा में डेटा उत्पन्न करती हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डेटा विज्ञान इस कच्चे, उच्च-गति, उच्च-मात्रा वाले डेटा को क्रियाशील जानकारी में बदलते हैं, जिससे परिवहन प्रणालियां पूर्वानुमानित, अनुकूली और लचीली बनती हैं। यह बदलाव भारत में विशेष रूप से स्पष्ट है, जहां बड़े पैमाने पर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और नई अवसंरचना परियोजनाएं गतिशीलता और लॉजिस्टिक्स की योजना तथा संचालन को नए सिरे से परिभाषित कर रही हैं।

शहरी और राजमार्ग गतिशीलता में, मशीन लर्निंग से संचालित बुद्धिमान परिवहन प्रणालियां (आईटीएस) यातायात और टोल संचालन में तेज़ी से केंद्रीय भूमिका निभा रही हैं। फास्टैग एक प्रमुख उदाहरण है, जिसने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रह को डिजिटल कर वाहन आवाजाही, यातायात घनत्व और गलियारे के उपयोग पर वास्तविक समय का डेटा उत्पन्न किया है। यह डेटा यातायात भीड़ विश्लेषण, गतिशील यातायात प्रबंधन और साक्ष्य-आधारित अवसंरचना योजना को सक्षम बनाता है। इसी प्रकार, कई भारतीय शहरों में तैनात एआई-सक्षम यातायात सिग्नल नियंत्रण प्रणालियां, सिग्नल समय को अनुकूलित करने, वाहनों के व्यर्थ रुकने के समय को कम करने और चौराहों पर सुरक्षा बेहतर बनाने के लिए लाइव कैमरा फीड और सेंसर डेटा का विश्लेषण करती हैं।

यूएलआईपी जैसे प्लेटफ़ॉर्मों पर लागू एआई और उन्नत विश्लेषण, बहु-माध्यमीय नेटवर्क में मांग पूर्वानुमान, मार्ग अनुकूलन और अवरोध पहचान को सक्षम बनाते हैं। ये क्षमताएं विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि भारत लजिस्टिक्स लागत कम करने और आपूर्ति शृंखला

की विशसनीयता बढ़ाने के लिए बहु-माध्यमीय लॉजिस्टिक्स पार्क, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित कर रहा है और समर्पित माल ढुलाई गलियारों का विस्तार कर रहा है।

एआई शेड्यूलिंग, ऊर्जा खपत, यात्री प्रवाह और रखरखाव योजना को अनुकूलित कर सकता है। जैसे-जैसे भारत उच्च गति रेल गलियारों की ओर बढ़ रहा है, उच्च गति पर सुरक्षा, समयनिष्ठा और परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए डेटा-आधारित नियंत्रण, वास्तविक-समय निगरानी और पूर्वानुमानित रखरखाव अनिवार्य हो जाएंगे। रेलवे, विमानन और राजमार्गों में एआई का सबसे प्रभावशाली अनुप्रयोग, पूर्वानुमानित रखरखाव है। ट्रैक, रोलिंग स्टॉक, सिग्नलिंग प्रणाली, पुल और विमान के पुर्जों के डेटा का विश्लेषण कर एआई मॉडल खराबी और फेल होने के शुरुआती संकेतों को पकड़ते हैं। इससे सुरक्षा बढ़ती है, सेवा व्यवधान कम होते हैं और अवसंरचना संपत्तियों की जीवनकाल लागत घटती है।

## 'विकसित भारत@2047' के लिए बहु-माध्यमीय परिवहन योजना और लॉजिस्टिक्स

हाल ही में प्रकाशित रिपोर्टें संकेत देती हैं कि भारत में लॉजिस्टिक्स लागत कम होने लगी है। अगली चुनौती केवल लागत घटाना नहीं, बल्कि उत्पादकता और अंतिम-छोर (लास्ट-माइल) डिलिवरी में सुधार करना है। इतिहास बताता है कि अकेले अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स में उत्कृष्टता नहीं लाती। जर्मनी की ताकत औद्योगिक समूहन से आती है। नीदरलैंड्स डिजिटल एकीकरण में उत्कृष्ट है। चीन ने अपनी अवसंरचना को औद्योगिक नीति और विनिर्माण रणनीति के साथ संरेखित किया है। प्रत्येक मामले में, अवसंरचना एक सहायक साधन था- अंतिम लक्ष्य नहीं।

लॉजिस्टिक्स दक्षता को इन मानकों से मापा जा सकता है:

- निर्बाध संचालन जो प्रथम-मील और अंतिम-मील दोनों के संपर्क को सुनिश्चित करे।
- आपूर्ति शृंखलाएं अधिक लचीली बन रही हैं।
- व्यवसाय कम सूची रखकर परिचालन रूप से अधिक कुशल हो रहे हैं।
- लॉजिस्टिक्स नेटवर्क सेवा वितरण और गुणवत्ता के मामले में अधिक उत्पादक हो रहे हैं।
- वस्तुएं अधिक पूर्वानुमानित ढंग से और डिलिवरी की गारंटी के साथ निर्धारित समय पर गंतव्य तक पहुंच रही हैं।

## एकीकृत परिवहन योजना की आवश्यकता

हाल ही में उद्घाटित गंगा एक्सप्रेसवे (मेरठ से प्रयागराज, 596 किमी) अपने मार्ग के साथ औद्योगिक और माल ढुलाई गलियारों को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो केवल एक परिवहन धमनी के रूप में सेवा करने से कहीं आगे जाकर, एक द्वि-उपयोगी अवसंरचना दृष्टिकोण को समर्थन देता है। बजट 2026 में तीसरे समर्पित माल ढुलाई गलियारे (दानकुनी से सूरत, 2150 किमी) और सात नए हाई-स्पीड गलियारों ('ग्रोथ कनेक्टर्स') की घोषणाएं इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम हैं।

सार्वजनिक नीति की दृष्टि से, भारत के अगले लॉजिस्टिक्स सुधारों में मॉडल संतुलन (सड़क माल ढुलाई बनाम रेल और जलमार्ग), भूमि-उपयोग योजना (औद्योगिक क्षेत्रीकरण, भंडारण समूह और शहरी माल ढुलाई योजना) और संस्थागत समन्वय (लॉजिस्टिक्स को नियंत्रित करने वाली कई एजेंसियों को एकीकृत करना) के माध्यम से प्रणाली दक्षता पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।

## एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना

'सम्पूर्ण क्षेत्र' दृष्टिकोण डेटा-आधारित एकीकृत परिवहन योजना में जारी है, जिससे साक्ष्य-आधारित अवसंरचना और राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान को सुदृढ़ किया जा सके तथा परिवहन मांग मॉडलिंग, माल प्रवाह विश्लेषण तथा परिदृश्य-आधारित पूर्वानुमान उपकरणों के

उपयोग के माध्यम से आगामी दशकों की परिवहन और लॉजिस्टिक्स मांग का आकलन किया जा सके।

यह एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजनाः

- भूमि उपयोग, शहरी विकास पैटर्न, राष्ट्रीय सुरक्षा अनिवार्यताओं, लचीलेपन-केंद्रित वित्तपोषण रणनीतियों और पर्यावरणीय चिंताओं के साथ अच्छी तरह से संरेखित होनी चाहिए।
- घरेलू परिवहन नेटवर्क को क्षेत्रीय, अंतरराष्ट्रीय और बहु-माध्यमीय (रेल, सड़क, बंदरगाह, वायु, पाइपलाइन, रोप-वे, जलमार्ग आदि) परिवहन और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क से जोड़ना चाहिए।

टिकाऊ और हरित लॉजिस्टिक्स को प्राथमिकता देनी चाहिए।

## 2047 की ओर बढ़ता भारत

देशभर में लॉजिस्टिक्स और गतिशीलता की अपेक्षाओं को मानकीकृत करने के लिए यह योजना सख्त तथा समयबद्ध पारगमन उद्देश्यों का पालन करेगी। विभिन्न मंत्रालयों के बीच योजना और क्रियान्वयन में बाधाओं को दूर करने के लिए और 'विकसित भारत@2047' की दिशा में हमारी यात्रा को गति देने के लिए, देश में एक एकीकृत परिवहन योजना प्राधिकरण की स्थापना की प्रक्रिया जारी है। ❑